

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—चपत्रण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

जावकार से जकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 142}

नई बिस्ली, शनिवार, ग्रप्नेल 30, 1977 वैशाख 10, 1899

No 142]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 30, 1977 VAISAKHA 10, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा का सर्व । Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April 1977

G.S.R. 207(E).—The following Proclamation by the President is published for general information

Whereas. I, Basappa Danappa Jatti. Vice-President acting as President of India, am satisfied that a situation has arisen in which the Government of Orissa cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution of India (hereinafter referred to as "the Constitution");

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by article 356 of the Constitution and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I—

- (a) assume to myself as President of India all functions of the Government of the said State and all powers vested in or exercisable by the Governor of that State,
- (b) declare that the powers of the Legislature of the said State shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and

- (t) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely:—
 - (i) in the exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation as aforesaid, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Governor of the said State.
 - (ii) the operation of the following provisions of the Constitution in relation to that State is hereby suspended, namely:
 - so much of the proviso to article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State.
 - so much of clause (2) of article 151 as relates to the laying before the Legislature of the State of the report submitted to the Governor by the Comptroller and Auditor-General of India;

articles 163 and 164,

- se much of clause (3) of article 166 as relates to the allocation among the Ministers of the business of the Government of the State; article 167 and so much of clause (1) of article 169 as relates to the passing of a resolution by the Legislative Assembly of a State;
- •lause (1) and sub-clause (a) of clause (2) of article 174, articles 175 to 178 (both inclusive); clauses (b) and (c) of article 179 and the first proviso to that article and articles 180 and 181,
- so much of article 186 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly; articles 188, 189, 193, 194, 195 and 196; article 198, clauses (3) and (4) of article 199;
- so much of clause (3) of article 202 as relates to the salaries and allowances of the Deputy Speaker of the Legislative Assembly; articles 208 to 211 (both inclusive), the proviso to clause (1) and the proviso to clause (3) of article 213; and
- so much of clause (2) of article 323 as relates to the laying of the report with a memorandum before the Legislature of the State;
- (iii) the Legislative Assembly of the said State is hereby dissolved,
- (iv) any reference in the Constitution to the Governor shall in relation to the said State be construed as a reference to the President, and any reference therein to the Legislature of the State or the Houses thereof shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and, in particular, the references in article 213 to the Governor and to the Legislature of the State or the House thereof shall be construed as references to the President and to Parliament or the Houses thereof respectively:

- Provided that nothing nerein shall affect the provision of article 152, articles 155 to 159 (both inclusive), article 299 and article 361 and paragraphs 1 to 4 (both inclusive) of the Second Schedule or prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Governor of the said State,
 - (v) any reference in the Constitution to Acts or laws of or made by the Legislature of the State shall be construed as including a reference to Acts or laws made, in exercise of the powers of the Legislature of the State, by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution, and the Orissa General Clauses Act, 1937 (Orissa Act 1 of 1937), and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), as applies to State laws, shall have effect in relation to any such Act or law as if it were an Act of the Legislature of the State

New Delhi,

B D. JATTI.

The 30th April, 1977

Vice-President acting as President.

[No. V/11013/3/77-S&F(DV)]

New Delhi.

T. C. A. SRINIVASAVARADAN Secy.

The 30th April, 1977

ORDER

New Delhi, the 30th April 1977

G.S.R. 208(E).—The following Order by the President is published for general information:

In pursuance of sub-clause (1) of clause (c) of the Proclamation issued on this the 30th day of April, 1977, by me under article 356 of the Constitution of India, I hereby direct that all the functions of the Government of the State of Orissa and all the powers vested in or exercisable by the Governor of that State under the Constitution or under any law in force in that State, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Governor of the said State

New Delhi; The 30th April, 1977 B. D. JATTI, Vice-President acting as President.

[No. V/11013/3/77-S&P(DV)]

New Delhi; The 30th April, 1977.

T. C A. SRINIVASAVARADAN, Secr.

पृह मंत्रालय

ग्रधिसूचना

नई दिल्ली, 30 **मप्रैल**, 1977

सा॰ का॰ मि॰ 207 (घ्र).—राष्ट्रपति द्वारा जारी की मई निम्नलिखित उद्घोषणाः सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है

यतः मेरा, भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति बसप्पा दानप्पा जलीः का समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें कि उडीसा राज्य का शासन भारत के सिषधान (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'सविधान' कहा गया है) के उपवन्धों के धनुसार नहीं चलायाः जा सकता है;

भ्रतः भ्रव मैं, सविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शिवतमो का तथा उस निमित्त मुझेः समर्थ बनाने वाली भ्रन्य सभी शिवतयो का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उद्घोषणा करता ह कि मैं:—

- (क) उक्त राज्य को सरकार के सभी कृत्य भौर उस राज्य के राज्यपाल में निहित या एतद्द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां, भारत के राष्ट्रपति के रूप में भ्रपने हाथ में लेता हूं,
- (ख) घोषित करता हूं कि उक्त राज्य के विधान मडल का शक्तियां संसद् के प्राधिकार द्वारा या श्रधीन प्रयोकतब्य होंगी; श्रौर
- (ग) निम्नलिखित श्रानुपिक श्रीर पारिणामिक उपबन्ध करता हूं ओ इस उदधोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिये मुझे श्रावश्यक या वाछनीय प्रतीत होते हैं; श्रर्थात् .--
 - (1) इस उद्योषणा के उपर्युक्त खंड (क) के भ्राधार पर भ्रपने हाथ में लिये गए कृत्यो भौर शक्तियो का प्रयोग करने में, मेरे लिये भारत के राष्ट्रपति के रूप में उस सीमा तक जिस तक में ठीक समझू उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करना विधिपूर्ण होगा;
 - (ii) उस राज्य के संबंध में संविधान के निम्नलिखित उपबंधों के प्रक्तिंन का एतद्द्वारा निलम्बित किया जाता है, प्रर्थात् :—
 - अनुच्छेद 3 के परन्तुक का उतना भाग जितने का संबंध राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधान मंदलको निर्देश करने से है;

- भनुष्ठित 151 के खंड (2) का उतना भाग जितने का संबंध भारत के नियंत्र ह महालेखा परीक्षक द्वारा राज्यपाल को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के राज्य विधान मंडल के समक्ष रखे जाने से हैं;
- भनुष्छेद 163 भौर 164,
- भनुष्छेद 166 के खंड (3) का उतना भाग जितने का संबध राज्य सरकार के कार्यों का मिलयों के बीच भावटन से हैं; अनुष्छेद 167 और अनुष्छेद 169 के खंड (1) का उतना भाग जितने का संबध राज्य की विधास्त्रा स्था द्वारा सकल्प के पारित किये जाने से हैं,
- भनुष्छेद 174 का खड (1) भौर खड (2) का उपखंड (क), श्रनुष्छेद 175 से 178 तक (जिसमें ये दोनो सम्मिलित हैं), श्रनुष्छेद 179 का खड (ख) श्रौर (य) श्रौर उस श्रनुष्छेद का प्रथम परन्तुक श्रौर श्रनुष्छेद 180 श्रौर 181,
- भनुच्छेद 186 का उतना भाग जितने का सबंध विधान सभा के उपाध्यक्ष के सन्ताों भौर भत्तों से हैं; अनुच्छेद 188, 199, 193, 194, 195 तथा 196; अनुच्छेद 198, अनुच्छेद 199 का खड़ (3) और खड़ (4);
- मनुष्छेद 202 के खंड (3) का उतना भाग जितने का सबध विधान सभा के उपाध्यक्ष के संबलमो भीर भत्तों से है; भ्रनुष्छेद 203 से 211 तक (जिसमे यह दोनों सम्मिलित है); भ्रनुष्छेद 213 के खंड (1) का परन्तुक भीर खंड (3) का परन्तुक; भीर
- प्रनुष्छेद 323 के खड (2) का उतना भाग जितने का संबंध ज्ञापन सहित रिपोर्ट के राज्य के विधान मडल के समक्ष रखे जाने से हैं;
- (iii) उक्त राज्य की विधान सभा एतद्वारा विश्वटिन की जाना है,
- (iv) सिवधान में राज्यपाल के प्रति किसी निर्देश का ग्रर्थ उस राज्य के सबध में राष्ट्रपति के प्रति निर्देश लगाया जा गा श्रीर उसमें राज्य के विधानमंडल या विधान सभा के प्रति किसी निर्देश का, जहां तक उस का संबंध उसके कृत्यों श्रीर उसकी गिक्तयों से हैं, श्रर्थ जब तक कि सदर्भ में श्रन्यथा भपेक्षित नहीं, संसद् के प्रति निर्देश लगाया जायगा, श्रीर विशिष्टतया भनुच्छेद 213 में राज्यपाल श्रीर राज्य के विधान मंडल या विधान सभा के प्रति निर्देश का श्रर्थ क्रमशः राष्ट्रपति श्रीर ससर् या उसके सदनों के प्रति निर्देश लगाया जा गा ।

परन्तु इसमें की कोई बात मनुष्छेद 153, अनुष्छेद 155 से लेकर अनुष्छेद 159 तक (जिसमें ये दोनो भी सम्मिलत है), अनुष्छेद र्ि 299 और अनुष्छेद 361 तथा दितीय अनुसूष्णे के पैरा 1 से लेकर पैरा 4 तक (जिसमें ये दोनों भी सम्मिलत हैं) के उपबंधो पर प्रभाव नही डालेंगे और न राष्ट्र-पित को इस खड के उपखड़ (1) के अधीन उस सीमा तक जहां तक वह शिक समझें, उक्त राज्य के राज्यपाल के माध्यम से कार्य करने से निवारित करेगी,

(V) संविधान में राज्य के विधान महल के या एतद्द्वारा बनाये गये अधिनियाों या विधियों के प्रति किसी निर्देश का ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो उसकेश इस उद्घोषणा के आधार पर संसर् द्वारा या राष्ट्रपति या सविधान के प्रमुच्छेद 357 के खड़ (1) के उपखड़ (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी द्वारा राज्य के विधान मंडल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाये गये अधिनियमों या विधियों के प्रति निदेश है, और उड़ीसा साधारण खड़ अधिनियम, 1937 (उड़ीसा 1937 का अधिनियम 1) और साधारण खड़ प्रधिनियम 1897 (1897 के 10वे) का उतना भाग जितना राज्य विधियों पर लागू है, ऐसे किसी अधिनियम या विधि के बारे में ऐसे प्रभावी होगा भानो यह उस राज्य के विधान मंडल का अधिनियम हो।

न**ई** विल्ली, -30 **प्र**प्रल, 1977 यसप्पा दानप्पा जत्ती, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उप-राष्ट्रप**िस** ।

न**ई** दिल्ली; 30 म्रप्रैल, 1977 [सं० $\mathrm{V}/11013^{\dagger}3/77$ -एस एड पी (डी- $\mathrm{V})$] टी० सी० ए० श्रीनिवासवरदन, सन्बिब ।

भावेश

नई दिल्ली, 30 म्रप्रैल, 1977

सा० का० नि० 208 (भ्र).—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित भाषेत्र कर्ने साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है:

भारत के संविधान के ग्रनुच्छेद 356 के ग्रधीन मेरे द्वारा ग्राण 1977 को ग्रप्रैण के सीसवे दिन जारी की गई उद्धीषणा के खंड (ग) के उपखंड रू(1) का ग्रनुसरण करते हुए

में एतद्द्वारा निदेश देता हूं कि उड़ीसा राज्य सरकार के सभी कृत्य और संविधान के अधीन या उ राज्य हे प्रश्नुत कि ती विधि के प्रशीन उन राज्य के राज्य में निर्देश व प्रशीक्तक सभी शक्तियां, जिनको राष्ट्रपति ने उक्त उद्घोषणा के खंड (क) के घाघार पर भपने हाथ में ले लिया है, राष्ट्र-कित के भधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अध्यक्षीन रहते हुए, उक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा भी प्रबोक्तव्य होगी।

नई विल्ली, **३० भ**प्रैल, 1977 बसप्पा वानप्पा जत्ती; राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उप-राष्ट्रपति ।

नई दिल्ली. **३० म**प्रल, 1977 [सं॰ VI/11013'3'77-एस एंड पी (डी-VI)] टी॰ सी॰ ए॰ श्रीनिवासवरदन, सजिब ।